RAJYA SABHA

Tuesday, the 21st August, 2001/30th Sravana, 1923 (Saka)

The House met at eleven of the clock, **Mr. Chairman** *in the Chair.*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

कॉफी उत्पादकों के लिए लाभकारी मूल्य

*401. **श्री रमा शंकर कौशिक:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश में कॉफी उत्पादकों को उनकी कॉफी की पैदावार का जो मूल्य मिल रहा है वह उसकी उत्पादन लागत से भी कम है और कॉफी का वर्तमान मूल्य गत वर्ष की तुलना में आधा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार कॉफी का उचित मूल्य दिलाने हेतु कौन-कौन से कदम उठा रही है; इसकी समय-सीमा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। हाल ही में कॉफी उत्पादक देशों द्वारा कॉफी का बेशी उत्पादन किए जाने के कारण मांग और आपूर्ति के बीच अंतर आया है और विश्व-बाजार में तथा घरेलू बाजार में भी कॉफी की कीमतों में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। इस प्रकार कॉफी के उत्पादकों को उनके उत्पाद की वह कीमत नहीं मिल रही है जो उन्हें 2-3 वर्ष पहले मिलती थी। कॉफी विपणन क्रियाकलापों के उदारीकरण के साथ, व्यापार गैर-सरकारी लोगों के पास है और कॉफी की कीमतों का निर्धारण मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा होता है।

तथापि, कॉफी के उपजकर्त्ताओं के लाभ के लिए भारत सरकार कॉफी बोर्ड के जरिए, अनेक योजना स्कीमें चला रही है और विकासात्मक क्रियाकलाप शुरू कर रही है जिनका उद्देश्य कॉफी की उत्पादकता में, विशेष रूप से लघु उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि करना तथा उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करना है ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्द्धात्मकता प्राप्त की जा सके। बोर्ड द्वारा

विशिष्टता कॉफी की उत्पादन करने के लिए बड़े उत्पादकों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है जिससे यू॰एस॰ए॰ और यूरोपीय संघ जैसे विकसित देशों में आकर्षक आय प्राप्त होती है। इन सभी उपायों से दीर्घकाल में कीमतें स्थिर होने की आशा है तथा उपजकर्त्ताओं को लाभकारी आय प्राप्त होना सुनिश्चित होगा।

Remunerative Price for Coffee Growers

†*401. SHRI RAMA SHANKER KAUSHIK: Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government are aware that coffee growers in the country are getting price for their coffee which is even less than the cost involved in production and the present price is half of the last year's price; and

(b) if so, the steps being taken by Government to provide reasonable price together with the time-frame thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI DIGVIJAY SINGH): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

( ) and (b) Yes, Sir. In the recent times, due to surplus coffee production by producing countries leading to a mismatch between demand and supply, the prices of coffee both in global and domestic markets have been witnessing a downward trend. As such, the coffee growers are not getting the same price for their produce which they were getting 2-3 year ago.

With the liberalisation of coffee marketing activities, the trade is in private hands and the prices of coffee are determined by market forces of demand and supply.

However, for the benefit of coffee growers, the Government of India, through Coffee Board, are operating several plan schemes and undertaking developmental activities aimed at increasing productivity of coffee particularly in the small grower sector and improving quality

---

†Original notice of the question was received in Hindi.

of the product to achieve competitiveness in the international markets. The Board is also encouraging the large growers to produce speciality coffees which fetches attractive premiums in developed countries like USA and European union. All these steps are expected to stabilise the prices in the long run and ensure remunerative return to the growers.

श्री रमा शंकर कौशिक: श्रीमन् माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि घरेलू बाजार में भी काफी की कीमतों में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। श्रीमन् गिरावट की प्रवृत्ति नहीं है बल्कि छोटे किसानों के साथ ज़बर्दस्त अन्याय हो रहा है। मिसाल के लिए मैं बताना चाहता हूं कि जो काफी की किस्म ए है, जिसकी कीमत सन् 97 में 131.48 रुपए रति किलो थी, उसकी कीमत 2001 में 56.31 रुपए प्रति किलो हो गई है, यानी एक तिहाई के करीब हो गई। इसी प्रकार से अरैबिका 'एबी' किस्म की कीमत 1997 में 100.66 रुपए थी, वह अब 45.58 रुपए प्रति किलो है। रूबस्ता चैरी एबी की कीमत 1997 में 65.25 रुपए थी, उसकी कीमत 2001 में 26.61 रुपए प्रति किलो हो गई है। इतनी जबर्दस्त गिरावट है और माननीय मंत्री जी को केवल यह प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी को यह जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे देश में जितना भी काफी का उत्पादन होता है, उसको डेढ़ लाख छोटे किसान ही पैदा करते हैं, कोई बड़ा काश्तकार नहीं है, छोटे किसान हैं और माननीय मंत्री जी कहते हैं कि बाजारी शक्तियों के आधार पर उसकी कीमतों में गिरावट हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कृपया छोटे किसानों के हित को संरक्षित करने के लिए, उन्हें उनकी उपज का वाजिब पैसा दिलाने के लिए आप बाजारी शक्तियों पर कुछ अंकुश रखने का प्रयत्न करेंगे और यदि करेंगे तो वह क्या है?

श्री दिग्विजय सिंह: माननीय कौशिक जी का प्रश्न बिल्कुल सही है। यह बात सही है कि पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी की कीमत घटी है और खास कर के 1997-98 के बाद काफी की कीमत लगातार घटती चली जा रही है और जो लोग काफी उगाते हैं, उनके बारे में जो आपकी प्रतिक्रिया है, वह स्वाभाविक है और मैं उससे सहमत हूं कि लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन यह बात भी उतनी ही सही है कि हमारी देश की 80 फीसदी काफी दुनिया में बाहर के देशों में जाती है और 20 प्रतिशत काफी का ही हम अपने देश में इस्तेमाल करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार उसके नियम को निर्धारित भी करता है, इसलिए उस पर बहुत ज्यादा हमारा नियंत्रण नहीं है। लेकिन आपने जो छोटे किसानों का सवाल उठाया, यह बात सही है कि 90 फीसदी काफी उगाने वाले छोटे किसान हैं जिनका 10 एकड़ से नीचे का प्लांट है, ग्रोअर इसी के आसपास के हैं, हालांकि वे 60 फीसदी ही काफी का उत्पादन कर पाते

हैं, 40 फीसदी काफी का उत्पादन बाकी जो बड़े 10 परसेंट बचे हुए हैं, उनकी ओर से होता है। लेकिन उनके लिए हमारे मंत्रालय की तरफ से एक मैकेन्ज़ी कमेटी की रिपोर्ट आई है जिसमें हमने कुछ बातों को तय किया है कि कैसे इन चीजों को बेहतर बनाया जाए और जो मार्जिनल फार्मर हैं, जो छोटे किसान हैं, उनको कैसे फायदा दिलाया जाए और उसी सिलसिले में दो, तीन, चार प्रस्ताव भारत सरकार ने दिए हैं उनमें एक प्रस्ताव है कि पैदावार कैसी बढ़ाई जाए, दूसरा है कि काफी बाजार में जो प्रतियोगिता है, उसमें उनको कैसे हिस्सेदार बनाया जाए, तीसरा है कि पैदावार बढ़ाने के साथ-साथ जो यूरोपियन बाजार या यू॰ एस॰ ए॰ का बाजार है, उसमें कैसे उनको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा दिलवाया जाए, इसकी तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की प्रक्रिया है, उसमें उनको कैसे हिस्सेदार बनाया जाए। ये कुछ सुझाव मैकेन्ज़ी कमेटी की तरफ से आए हैं, जिनको हमारे मंत्रालय ने स्वीकार किया है।

श्री रमा शंकर कौशिक: श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकारा है कि 80 फीसदी हमारे यहां जो काफी उत्पादित होती है, वह बाहर जाती है, उसका निर्यात होता है और यह भी माननीय मंत्री जी ने स्वीकारा है कि छोटे किसान ही ज्यादा काफी पैदा करते हैं और बावजूद इसके कि हमारे निर्यात में कहीं कोई कमी नहीं आई है, लेकिन बाजारी शक्तियां, निर्यात करने वाले लोग मुनाफा कमाते हैं। खैर यह अलग बात है। मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी हाल ही में कॉफी उत्पादकों का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला था और उन्होंने यह मांग की थी कि जो कॉफी को सुधारने के लिए या कॉफी के उत्पादन में आवश्यक चीजें होती हैं, उसके लिए कुछ चीजें बाहर से मंगाई जाती हैं जैसे पलपल, मूसीलेह, रिमूवर, पी॰ पी॰ कैमिकल, कलर सॉर्टर बैंडिंग मशीन आदि, इन चीजों पर माननीय मंत्री जी ने भारी आयात शुल्क लगा दिया है। उन लोगों ने यह मांग रखी थी कि आयात शुल्क ज्यादा से ज्यादा 10 प्रतिशत होना चाहिए, तभी छोटे किसानों को लाभ हो सकता है। दूसरी मांग उन्होंने यह की थी कि उनको जो ऋण दिया जाता है, वह आसान किश्तों पर दिया जाना चाहिए, सावधिक अवधि के लिए दिया जाना चाहिए और उसकी वसूली 10 वर्षों में होनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि 'ग्रीन बाक्स' की व्यवस्था WTO के नियमों में है, इसलिए 'ग्रीन बाक्स' के नाम पर आप छोटे किसानों को सब्सिडी दे सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ग्रीन बाक्स व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार क्या करने जा रही है? जो आयात शुल्क बढ़ा है, क्या सरकार उसे 10 प्रतिशत करने पर विचार कर रही है? क्या सरकार उन किसानों को सावधिक ऋण मुहैया कराने और 10 वर्षों में उसकी वसूली करने पर विचार कर रही है?

श्री दिग्विजय सिंह: माननीय सदस्य का पहला सवाल तो वित्त मंत्रालय से संबंधित है,

वह हमसे जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन हम हर उस प्रयास का समर्थन करेंगे जिससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़े और इसके लिए हम वित्त मंत्री जी से सादर निवेदन करेंगे कि ...(**व्यवधान**) अल्टीमेटली तो यह एक्सपोर्ट ही होगा ना, 80 फीसदी एक्सपोर्ट होना है, इसलिए मैं उसका समर्थन करता हूं। जहां तक सरकार की तरफ से उनकी मदद किए जाने की बात है, पिछले वर्ष हम लोगों ने करीब 10 करोड़ रुपए के आस-पास जो पैनल ऋण का इंटरेस्ट उन पर लगा था, उसको हमने माफ किया है जिससे छोटे काश्तकारों और कॉफी ग्रोअर्स को काफी राहत मिली है। आपके सुझावों के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड पहले से ही इस पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं और उनको सहायता देने के लिए अपनी तरफ से कदम उठा रहे हैं।

SHRI S.R. BOMMAI: Sir, Karnataka produces almost 75 per cent of the coffee in this country. I would like to know from the hon. Minister whether the Government, through the Coffee Board, would intervene and try to purchase coffee, particularly, from the small farmers so that they can survive.

SHRI DIGVIJAY SINGH: Mr. Chairman, Sir, as the hon. Member, Bommai Saheb, has correctly said, Karnataka is the largest producer of coffee in the country. Seventy-two per cent of the coffee is produced by Karnatka. Till 1994-95, the Coffee Board used to do this business, as you have been mentioning. But now, we do not have any intention to do that because, after liberalisation, the market is free and people are doing it on their own.

सरदार बलविन्दर सिंह भुंडरः सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात तो मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में मान ली है कि कीमतें बहुत कम हैं। इन्होंने अपने उत्तर मैं यह भी कहा है कि हम 3-4 स्टैप्स ले रहे हैं जिससे क्वालिटी अच्छी हो, वे यील्ड अच्छी दें और मार्केट को हम ऐसे एप्रोच करें कि किसानों की मदद हो। यह बातें तो हम भी कहते हैं और मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं लेकिन तथ्य यह है कि 3 साल से हमारी फसलें फेल हो रही हैं—पहले फूडग्रेन्स की क्रॉप फेल हुई, फिर वैजिटेबल्स की क्रॉप फेल हुई और अब कॉमर्शियल क्रॉप्स जैसे कॉफी, चाय आदि फेल हो रही हैं और सरकार भी इस बात को स्वीकार कर रही है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इसके लिए क्या आप कोई टाइम-बाउंड प्रोग्राम एनाउंस करेंगे कि हम ये-ये कदम इतने दिनों में उठाएंगे ताकि ये जो कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं, ये फेल न हों और देश के 70 प्रतिशत

किसान और मजदूर भुखमरी की स्थिति में न पहुंचें और देश में और ज्यादा बरबादी न हो। इसलिए आपने जो ये तीन-चार बातें कही हैं, उनको टाइम-बाउंड करना चाहिए। इसके साथ मैं एक बात और जानना चाहता हूं क्या यह भी साफ करने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट बोर्ड को कोई ऐसी हेल्प करेंगे कि जब बफर स्टॉक वगैरह हो जाए या सरप्लस को जाए तब दूसरे फील्ड में उसकी रेम्यूनिरेटिव प्राइसेज गिर सकें? कृपया इसका उत्तर देने का कष्ट करें।

श्री दिग्विजय सिंह: माननीय सभापति जी, अंतर्राटरीय बाजार में कीमतें घटी हैं और उसी का परिणाम यहां भी हुआ है और जैसा माननीय सदस्य ने स्वयं कहा कि कीमतें बहुत घटी हैं और उसका असर हमारे ऊपर भी हुआ है। जैसाकि पहले ही बताया कि 80 फीसदी कॉफी हम बाहर भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और बाजार का नियंत्रण बाहर से ही ज्यादा होता है। हम अपनी तरफ से क्या-क्या कदम उठा सकते हैं वह अपने जवाब में भी मैंने कहा है और माननीय सदस्य के उत्तर में भी कहा है। अब उसके बदले में कोई टाईम बाउंड स्कीम के बारे में कि हम इतने समय में इसको पूरा करेंगे यह तो बाजार की जरूरत के हिसाब से ही तय किया जा सकता है और जैसे-जैसे जिसकी जरूरत पड़ेगी हम उस हिसाब से उस काम को करने के लिए तैयार हैं।

SHRI SHANKAR ROY CHOWDHURY: Sir, I agree with the hon. Minister that the prices of coffee, like the prices of palm oil, are determined by the international market prices, but, in the process, as the Government is well aware, the small farmers are getting ruined in many sectors. Now, we are talking about coffee. The hon. Minister has announced several steps which the Government proposes to take. Hon. Member, Rama Shankerji, has particularly mentioned about the incentives for coffee growing which the Government is planning. I would like to know whether the hon. Minister is aware that these steps are being proposed for the last several years, but they have not yet been put into effect, including, particularly loans from NABARD, which the hon. Minister just now mentioned. I would like to know what steps the Government is taking in this case to ensure that our coffee growers, who are, as he said, 90 per cent private, are not totally ruined, as has been happening in other countries like Kenya.

SHRI DIGVIJAY SINGH: Sir, as prices are related to demand, the Coffee Board has drawn up a medium-term export strategy, by engaging a private consultant, Mekenzy & Company for increasing India's share in the world coffee market. The strategy includes:

No. 1, shifting the product-mix in favour of Arabica from the present emphasis on Robusta; No. 2, ensuring competive landed price for Indian coffee, by aggressively bringing down the growing cost by improving yields; No. 3, improving the consistency in the quality of exported coffee; No. 4, guaranteed reliability of exporters; and No. 5, improving awareness of Indian coffee in target markets, like Italy, Germany and the United States of America, through aggressive communication efforts and increasing the size of export shipments.

MISS MABEL REBELLO: Sir, eversince the Coffee Board stopped buying coffee, I am told, a lot of exporters have started buying coffee from small growers in Karnataka. Most of them are exploiting the small growers. They tell them: "We will take your coffee and we will export. When the export realisation comes to us, we will pay." That means, when they get money, only then they will pay. During the last two or three years, a lot of small farmers have been exploited and duped like this. They have not at all paid them the coffee price. I would like to know whether the hon. Minister is aware of it or not. Two months ago we had a discussion with the Coffee Board Chairman and he said that they were aware of this State of affairs. If the hon. Minister is aware of it, what does he intend to do? Will he try to get these exporters pay the small growers.

SHRI DIGVIJAY SINGH: Sir, we are aware of it. Recently, at the behest of the Government of India, the RBI and NABARD have issued instructions to the commercial and cooperative banks to reschedule the crop loans of the coffee growers and also to extend them phased working capital loans, as a relief to the coffee growers. These are the steps that I have taken. As I have mentioned earlier also, in March...

MISS MABEL REBELLO: For the last two or three years, these small farmers are not getting their money at all. They have given their commodities to these exporters and the exporters have made money out of it.

SHRI DIGVIJAY SINGH: Firstly, when they had given their money to the exporters, they did not consult us.

MISS MABEL REBELLO: Do you want them to fend for themselves? The Government is supposed to regulate the system. You want the small farmers to fight with big brothers? Is that the reason you dismantled the system so that the small farmers are exploited?
Sir, is this the answer? Are you not encouraging the exporters? You want big people to become rich.

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल: सभापति महोदय, हम भी प्रश्न का जवाब सुनना चाहते हैं। ...**(व्यवधान)**...

MISS MABEL REBELLO: Sir, it has been said in the written reply also. "The Board is also encouraging large commerce." They are only looking after the large commerce and their interests. The small farmers, the small man are not in the reckoning of this Government at all.

SHRI DIGVIJAY SINGH: Mr. Chairman, Sir, as I said, the Government is aware of every situation which the hon. Member has just mentioned. I am trying to point out what intention we have in our mind. I have explained the Government's intention, the Ministry of Commerce's intention and what we are planning to do. That is all. ..*(Interruption)*...

श्री नरेन्द्र मोहन: सभापति महोदय, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह सटीक अवश्य है। लेकिन समस्या यह है कि भारतीय काफ़ी की न तो उत्पादकता बढ़ पा रही है और न ही उसकी गुणवत्ता में वह वृद्धि हो रही है जिससे उसकी खपत और बढ़ सके। सभापति महोदय, भले ही मैकिंजे कमेटी की रपट आ गई हो, लेकिन मंत्री जी कृपया करके बतायें कि उसकी उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़े इसके लिए पिछले दो-तीन वर्षों में कितना खर्च किया गया है और किसानों तक वह धन पहुंचा है या नहीं पहुंचा है? आज भारतीय काफ़ी की मांग अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। भारत का शेयर अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत कम है। इस स्थिति का निराकरण तो तब होगा जब गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ेगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसके लिए क्या किया जा रहा है?

श्री दिग्विजय सिंह: सभापति महोदय, जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा कि उत्पादकता कैसे बढ़ायी जाये। उत्पादकता का पिछले तीन-चार साल का आंकड़ा जब आप देखेंगे तो पायेंगे कि हर साल हमारा उत्पादन तो बढ़ा है।...**(व्यवधान)**...

श्री नरेन्द्र मोहन: उत्पादन तो बढ़ा है लेकिन उत्पादकता नहीं बढ़ी है। उत्पादन बढ़ना और प्रोडक्टिविटी पर-एकड़, पर-हैक्टर, What is your productivity? What is the yield?

श्री दिग्विजय सिंह: उत्पादकता और उत्पादन दोनों अलग-अलग चीजें हैं यह तो मैं जान ही रहा हूं। लेकिन मैं इतना आपको बता रहा हूं कि उत्पादन हमने हर साल बढ़ाया है। इसको बढ़ाया ही नहीं है, अगर आप आंकड़ा देखें तो 1997-98 में 2 लाख 28 हजार मैट्रिक टन था, आगे बढ़कर यह 2 लाख 65 हजार हो गया, उसके आगे बढ़कर 2 लाख 93 हजार हो गया और पिछले साल 2000-2001 में यह तीन लाख एक के करीब हो गया। ...(व्यवधान)...

SHRI NARENDRA MOHAN: What is your yield? What is the increase?

श्री दिग्विजय सिंह: वह भी मैं बताता हूं पहले आप उत्पादन तो सुन लें फिर मैं उत्पादकता बताता हूं। मेरा माननीय सदस्य से एक ही निवेदन है कि दुनिया के बाजार में काफी की कीमत घटती चली जा रही है और वह इतना घटी है कि करीबन-करीबन 80 फीसदी पर पहुंच गयी है। जहां हमें सौ रुपया मुनाफा होता था वहां आज मुनाफा हो रहा है 40, 50, 55, 60 के आसपास। इसलिए हमको इसकी जिम्मेवारी का भी निर्वहन करना है। जो लोग इसमें धन लगा रहे हैं उनको उतना पैसा ही मिल रहा है। आजकल करीबन 50, 55, 60 हजार के आसपास पर हैक्टर खर्च होता है उसको पैदा करने में और उतना ही उनको मिल रहा है। इसलिए हम इसकी उत्पादकता को बढ़ाने में अपनी तरफ से तो प्रयास कर ही रहे हैं लेकिन इनको बाजार से पैसा भी मिले यह भी हमारी जिम्मेवारी है। आज अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उसका ध्यान रखते हुए फिलहाल यह बहुत ज्यादा फायदे का काम हमें नहीं दिख रहा है।

श्री नरेन्द्र मोहन: सभापति महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल नहीं आया है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, आपको लाभ मिला या नहीं मिला, क्या भारत अपने प्रतिशत को और बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तैयार है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? ...(व्यवधान)...

श्री दिग्विजय सिंह: सभापति महोदय, जब मैं मैकिंजे रिपोर्ट का जिक्र कर रहा था तो उसमें इसी का जिक्र है—कैसे उत्पादकता को बढ़ाया जायेगा, कैसे दुनिया के बाजार में भारत अपना प्रवेश करेगा, इसी बात का जिक्र तो मैकिंजे रिपोर्ट में है।

श्री सी० एम० इब्राहीम: सर, अभी-अभी मंत्री जी ने मार्केट फोर्सेज़ का उल्लेख किया। मैं आपसे दो चीजें पूछना चाहता हूं। अमेरिका का किसान हिन्दुस्तान को दूध का पाउडर बेचता है

तो वहां की सरकार उसको एक हजार डालर की सबसिडी देती है। यहां तो आपने पूरी सबसिडी हटा दी है। यह ठीक है। लेकिन इसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो काफ़ी ग्रोअर्स फेडरेशन की तरफ से मांग रखी गयी थी कि जितनी इस पर एक्साइज ड्यूटी वगैरह लगायी गयी है क्या उसको हटाने की कोशिश आप करेंगे? नम्बर दो, आप मार्किट-मार्किट कहते हैं, शेयर बाजार में जब दाम गिरता है तो उसमें फोरन हुकूमत पैसा लगाना चाहती है। लेकिन जब किसान की चीजों के दाम गिरते हैं तो आप आगे नहीं आते हैं। जितना पैसा आप शेयर बाजार में लगाते हैं कम से कम उतना पैसा 50 फीसदी किसानों के लिए लगाने में सरकार की कोई नीति है?

श्री दिग्विजय सिंह: कॉफी से इस सवाल का कोई रिश्ता नहीं है।

Joint Working Group on Communications

*402. SHRI K.M. KHAN: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that India and Iraq have decided to form a Joint Working Group on Communications to explore the scope for co-operation;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the extent to which it would be helpful in promoting India's interests?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI TAPAN SIKDAR): (a) Yes, Sir.

(b) During the visit of Iraqi Minister of Transport and Communications in July, 2001, it was decided to set up a Joint Working Group consisting of India and Iraq. The nomination of persons on the Working Group will be finalised soon.

(c) Setting up of the Working Group will help both the countries, in the communication sector especially. It will expedite the process of cooperation between Iraq and India.

SHRI K.M. KHAN: Sir, India and Iraq have age-old friendly relations, and Iraq suffered, during the Gulf War, heavily, in different fields, including communications, and, therefore, the setting up of a Joint Working Group on Communications between Iraq and India is a good step, a positive step, in improving the bilateral